# साप्ताहिक समय माया

"पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं."

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\16730/12/1/97/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM



Tel : 91-731-2102725
Cell : 9300755803-9425125569
Fax : 91-731-2531630
Websites : www.corruption2india.com
www.geocities.com/corruption2india/eduIndore.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com


(c) all copyrights reserved with chief editor.

वर्ष 7 अंक 29 इन्दौर, जबलपुरसोमवार 3 अक्टूम्बर से 16 अक्टूम्बर 2005 (संयूक्तांक) पृष्ठ 8 मूल्य रु.2/-


2 ■आखिर आई.ए.एस. चुरकटों को ही बनाया सूचना अधिकारी
■ सूचना का अधिनियम व्यर्थ

3 ■ दास्ताने खाद्य एवं औषधि नियंत्रक
■ जिला पंचायतों के मु.का.अ. महाभ्रष्ट और जालसाज

4 ■ 35% बढ़ा ही दी कीमते पेट्रोल डीजल की
■ ए.के.वी.एन. भ्रष्ट डकैतों का अड्डा

5 ■ अनावश्यक जाँच के नाम, लूट के अड्डे
■ शिक्षक भर्ती फार्म 200 रु. टी.आई. रु. 1 में

6 ■ निगम के बंद होते ही सब की पौ बारह
■ सभी सटोरियों की कठपुतली

7 ■ काम हुआ रु.10 लाख का भुगतान रु.60 लाख
■ भ्रष्टाचार का प्रकोप


### बुश व ब्लेयर का दाना चुग भारत की

## बर्बादी पर तुले हैं सोनिया और मनमोहन

मनमोहन की अमेरिका यात्रा और ब्लेयर की भारत यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि वो मनमोहन और सोनिया से मिलकर देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुल मिलाकर हरामखोर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और ब्रिटेनी प्रधानमंत्री अपने हितों को सिद्ध कर 10 करोड़ की आबादी के देश की बढ़ती समृद्धि और सौदों को रोककर उसे पंगु बनाकर भिखारी बना रहने दें अन्यथा भ्रष्ट कांग्रेसियों की सरकार के पतन के साथ ही उनकी महाशक्ति का दबदबा एशिया से सिमट जाएगा इसलिए जब मनमोहन अमेरिका गया तो उसे परमाणु सैन्य क्षमता मानने का दाना डाला गया। फिर ब्लेयर भारत आया तो उसने 140 अरब रु. का निवेश कर दाना डाल पुराने इतिहास व्यापारी बन कब्जा कर शासक बनने का नाटक दोहराया।

सोनिया की कठपुतली मनमोहन को जब अपनी-अपनी औकात समझ आई तो सोंठ मार गया।

गिद्ध बुश और ब्लेयर नहीं चाहते कि ईरान से पाइप लाइन डाल कर गैस आपूर्ति भारत को मिले इसलिए पाकिस्तानी मुशर्रफ का दाना डाल कर और दबाव बनाकर सौदे को र-करवाने के प्रयास चल रहे हैं।

मनमोहन के सवा वर्ष के कार्यकाल में मनमोहन ने हर विदेश यात्रा में अति उत्साह में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री ब्लेयर के सामने घर के पालतू कुत्ते की तरह उनके टुकड़े पाकर और खाकर राष्ट्र के हितों को त्याग अपनी पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी का न केवल परिचय दिया वरन राष्ट्र के 110 करोड़ लोगों को भी उन्हीं का गुलाम सिद्ध किया है।

विश्व का अपने आप को दादा समझने वाले इस गुंडे बुश और उसकी रखैल ब्लेयर ने यदि 1 टुकड़ा डाला तो मनमोहन ने उनकी तीन टुकड़े निभाई। निःसंदेह अमेरिकी ब्रिटिश और यूरोपिय हितों को संरक्षक सोनिया ने अपने आपको देश की बहू बताकर अपने मायके यूरोप के हाथों आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक रूप से देश को हर कदम-कदम आर्थिक नुकसान पहुंचाया हाल ही में मनमोहन ने अमेरिका और इंग्लैंड की खातिर जिस ईरान से गैस पाइप लाइन लेने की बात की जा रही थी उसकी अंतराष्ट्रीय मंच से उनके टुकड़ों की खातिर देश के हितों को त्याग कर अनावश्यक आलोचना कर और संयुक्त राष्ट्र में उसके विरुद्ध परमाणु मु- पर वोटिंग कर ईरान से शत्रुता अमेरिकी दबाव में झुकने और उसकी बात मानने तक का वक्तव्य तक दे डाला।

सारी कहानी के पीछे अमेरिका और इंग्लैंड की नीति यह है कि किसी

शेष पृष्ठ 6 पर

### संघ और भाजपा को बर्बाद कर रहे

## संघ के धूर्त बुजुर्ग मराठे

### भाजपा अंतर्कलह में उलझ जनता में पैठ के मु- भूल रही

संघ के बुजुर्ग धूर्त नेता कभी इंदिरा के गुणगान करते हैं तो कभी इटालियन एजेन्ट सोनिया दाढ़ी चरणरज माथे से लगाकर जयश्रीराम का नारा लगाते हैं। इस पर भी कोई उनकी तरफ नहीं देखता है तो कभी आडवाणी को हड़काते हैं तो कभी अटल की छवि को धूमिल करने के लिए बांग देते हैं।

इस अंतर्कलह की वजह से पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर घोषणा वीर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर चुप हो जाते हैं तो देश के साथ नेहरू खानदान के केजीबी और सीआईए

शेष पृष्ठ 4 पर

## कांग्रेसी व कम्युनिस्ट जन्म से देशद्रोही

***नेहरू, माउंट बेटन की बीवी के साथ तो इंदिरा जिमी कार्टर के साथ व्हाइट हाउस में सोये हैं, कम्युनिस्ट तो विशुद्ध रसियन एजेंट हैं***

कांग्रेस की स्थापना भारत में रह रहे अंग्रेज ए.ओ. ह्यूमने 15 दिस. 1885 को कलकत्ता में, भारतीयों के अधिकारों के लिये की थी, ताकि वो संगठित होकर उनकी हुकूमत से बात कर सकें। शनैः-शनैः उसका स्वरूप बदलता चला गया और पढ़े-लिखे भारतीय जुड़ते चले गए। जवाहर लाल नेहरू केम्ब्रिज में पढ़े, गुण धर्म पूरे अंग्रेजों के थे। इंदिरा आक्सफोर्ड में पढ़ी। स्वाभाविक था। अंग्रेजों, यूरोप, अमेरिका, रूस से न केवल संबंध अच्छे रहे वरन नेहरू की दीवानगी लेडी एडविना से बिस्तर तक की दोस्ती थी। नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और सोनिया तक उसके इशारों पर और इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताशकंद में लालबहादुर शास्त्री की हत्या के बाद इंदिरा का प्रधानमंत्री बनना, सत्ता जाने के बाद मधुलिमये का रूस से लोटते ही मोरारजी सरकार गिराने तक में केजीबी का हाथ था। रसियन केजीबी अमेरिकन सीआईए तक की डबल एजेन्ट थी, इंदिरा। ऐसे ही सोनिया का भी हाल है। इसी कारण इंदिरा गांधी दुनिया की सर्वोच्च शक्ति केन्द्र अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास अमेरिका प्रवास के दौरान व्हाइट हाउस में सोयी प्रवास के दौरान व्हाइट हाउस में सोयी जब वहां राष्ट्रपति के रूप जिमी कार्टर सत्ता संभाल रहे थे। हाल ही में सोनिया व उसके परिवार के सदस्यों की रूस और अमेरिका यात्रा ने डबल एजेन्ट होने की भूमिका को पक्का कर दिया है। जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है तो पूरे बंगाल और केरल में अधिकांश धन रसिया से अभी भी आता है। ज्योति बसु जैसे दिग्गज नेता सरकार बंगाल की चलाते थे। गुण रुसी कम्युनिस्मवाद के गाते थे इन सारे हरामखोरों पर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा चलाया ही जाने चाहिए।

हाल में रसियन केजीबी पर लिखी पुस्तक में अधिकांश कांग्रेसी मंत्रियों और कम्युनिस्ट पार्टी को रूस ने घूस दी थी। रूस ने तो घूस नेहरू और इंदिरा को भी दी थी तभी रूस से नेहरू इंदिरा ने बेसिर-पैर की खराब तकनीकी की मशीनें खराब पड़ गई, पुरानी कबाड़

शेष पृष्ठ 2 पर

## स्कार्पियन और एयरबस में 10 से 20% कमीशन

**आखिर सत्ता में आते ही क्यों होते हैं हजारों करोड़ के कबाड़े के थोक सौदे**

सत्ता में आते ही अपनी मोटी कमाई के लिये जनता के धन से कैसे होली खेली जाती है और खेली जाती रही है प्रबुद्ध पाठक अच्छी तरह से समझते हैं।

जहाँ रक्षा मंत्रालय की बात उठथी है तो जनता और सुरक्षा की आड़ में जिन्हें जनता चुनकर पहुंचाती है वो राष्ट्र के भ्रष्ट गिद्ध कर्णधार हजारों करोड़ का कबाड़ा ही खरीद डालते हैं। जैसा कि आजादी के बाद से देश की सरकारों ने किया है। फिर जहाँ कांग्रेस की शूकरीय फौज हो तो कहना ही क्या। उसका तो अदना सा भी कार्यकर्ता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी इसलिये ही बनता है।

हाल ही में किये गये 7 स्कार्पियन पन डुब्बियों का सौदा जो रु. 13,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। उसके एक दिन पूर्व ही 10,000 करोड़ का एयर बस खरीदने का सौदा मनमोहन ने फ्रांस से किया था। रु. 23000 करोड़ में 10% भी कमीशन रु. 2300 करोड़ का होता है।

भाजपा ने भी रुसी जल सेना से बाहर किये गये एडमिरल गोशीकोव का सौदा रु. 6000 करोड़ में किया था जो 1987 से लेनिनग्राद बंदरगाह पर पड़ा सड़ रहा था।

हजारों करोड़ की खरीद में 10 से 25% कमीशन तक डकारने के लिए आंख मींच कर कबाड़ा त्रुटिपूर्ण समय बाधित, अनुपयोगी, पुरानी बेमतलब पुनडुब्बियों, एयर बस आदि के रु. 23000/- करोड़ के सौदे की भी मूल कहानी यही है। फिर हर सरकार की कमाई का यह बड़ा स्त्रोत होता है।

भारत के रक्षा संस्थानों, जल, झल व वायु सेना में विदेशों से आयात किये जाने वाले लड़ाकू वायुयान वाहक जलपोत, पनडुब्बियां, सुखोई 30, मिग 21 से लेकर मिग 29 तक, सीहेरियर जगुआर, मिराज 2000 से लेकर 1940-50 के दशक के लंबे एंटीना वाले वायरलेस सेट से लेकर लाइट मशीन गनें, स्टेनगनें से राडार तक अधिकांश तकनीकी जो रक्षा मंत्रालय खरीदता है। जब अमेरिकी, फ्रांस, ब्रिटानी, रसियन, इसरायली, सेनाओं से सेवा निवृत्त समय बाधित, चलन से बाहर, पुरानी, दोषपूर्ण हो जाने पर भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदी ही इसलिये जाती है कि उनमें 10 से लेकर 70% तक कमीशन डकारा जा सके। विदेशी सेनाओं के लिए तो वह कबाड़ा है जिसका कीमत फिर भी उन्हें अच्छी ही मिल जाती है। उन्हें उस कबाड़े का नष्ट करने में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए उन्हें 50 से 70% कमीशन भी देना पड़े तो उन्हें फिर भी फायदा ही मिलता है। फिर राजनेता को मुंह भर चलाना पड़ता है। लड़ेगी तो सेना मरेंगे तो उसके जवान ये तो वो हारे या जीते मरे या जियें इन्हें तो दिल्ली में बैठकर जनता के सीने पर हर तरीके से मूंग ही दलना है।

दूसरी ओर जब रेलें, सड़कें, निजी क्षेत्र में दी जा रही हैं। हवाई अड्डे बनाने, विकास करने, रखरखाव करने का काम निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइंस को क्यों शासकीय उपक्रम बनाकर रखा है। उसका भी निजीकरण करना ही है तो रु. 10000 करोड़ की एयर बसों का सौदा क्यों किया गया। मात्र 25 वर्ष से ज्यादा पुरानी तकनीकी की एयर बस जो वहां सड़ रही है। इसलिए बेची व मनमोहन द्वारा खरीदी जा रही है कि मोटा कमीशन मारा जा सके। जबकि

शेष पृष्ठ 2 पर

### प्रदेश में शिक्षक आत्महत्या कर रहे थे निवेश की आड़ में

## वो दिल बहलाने विधवा बहू को ले लंदन की सैर

प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदेश सरकार न केवल पेरदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है वरन शिक्षकों से मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि तरह दुश्मनों सा व्यवहार कर उन्हें बर्खास्तगी दे रही है, जिससे शिक्षकों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है।

एहसान फरामोश गिरगिटिया रंग बदलने वाला गौर सत्ता के मद में कितना मस्त है कि वो दिल बहलाने अय्याशी करने निवेशकों को आकर्षित करने के बहाने लंदन गया। अब जब वीडियो कान्फ्रेंसिंग ई-मेल जैसे विश्व व्यापी साधन उपलब्ध हैं तो क्या जरुरत है वहां जाने की। जब जनता का धन अय्याशी और मौज-मस्ती के लिए उपलब्ध है तो क्यों न फूंका जाए।

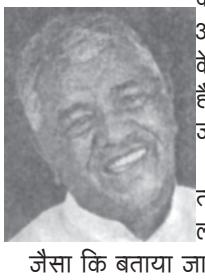

एक तरफ तो वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य अधिकारीगण अपने परिवार के सदस्यों के साथ जनता के खर्चे पर ऐशो आराम, अय्याशी के लिए किसी भी बहाने विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। कभी अध्ययन और व्यवस्थाओं के आंकलन केलिये तो कभी निवेश आकर्षित करने के लिए वहां होटलों में बैठकर या घूमने-फिरने और मौज-मस्ती में समय बर्बाद करने के अतिरिक्त क्या कर पा रहे हैं जबकि उस देश की साइटें इंटरनेट पर खोल कर अध्ययन, निवेश आकर्षण, कंपनियां या उनके प्रतिनिधियों से बातचीत सब कुछ किया जा सकता है, परन्तु इन भ्रष्ट निकम्मों की आदत तो कांग्रेसी सरकारों कीतरह कर्ज लेकर घी पीने की पड़ चुकी है। इनकी

शेष पृष्ठ 2 पर

साप्ताहिक समय माया

## संपादकीय

### महाभ्रष्ट, डकैत ही बना दिये सूचना अधिकारी

# सूचना का अधिनियम व्यर्थ

*विधायिका वाह वाही के लिये कानून बनाती हैं। जान बूझकर छेद भी बनाती ही हैं, ताकि न्यायाधीश और वकील अपने लोगों को बचा सकें। फिर न्यायाधीश भी वेतन तो न्यायालय जाने आने का लेते हैं। न्याय तो उन्ही को देगे जो धन देगा जो धन देगा स्वाभाविक हैं, न्याय, अन्याय होकर भी उसके पक्ष में जायेगा, क्योंकि कानून विधायिका ने बनाया ही ऐसा था, और बनाया ही ऐसा जाता हैं।*

*हाल ही में बनाया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी बनाया गया। केन्द्र शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्र व राज्य सरकार में बनाने की व्यवस्था की।*

*म.प्र. की राज्य सरकार ने इस कानून के अंतर्गत चूंकि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना था इसलिये उन्ही महाभ्रष्ट और डकैतों को ही सूचना आयुक्त बना दिया। अब महाभ्रष्टों और शासन की जमीनों और जनता के धन पर डाका डालने वाले अरबों डकारने वाले राजस्व आयुक्त बतायेंगे कि उन्होने कितने करोड़ कमाकर शासन के कितने अरब डुबो दिये या शासन की जमीनों को जो अरबों रुपयों की थीं, कितने करोड़ जेब में रखकर ठिकाने लगा दीं। फिर शासन के जिन भ्रष्टों के विरुद्ध सूचनायें मांगनी व जनता को चाहिये वहीं जब जिला, संभागीय और राज्य स्तर के ही अधिकारी होगें तो अधिनियम को ही व्यर्थ बना दिया गया क्यों कि व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।*

*विधायिका व्दारा बनाये गये इन्ही छेदों के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही महाभ्रष्ट, निकम्मी, मक्कार, कामचोर हो चुकी हैं। निरर्थक हैं ऐसे कानून बनाना।*

*फिर म.प्र. शासन का राज्यपाल भी हैं, तो पुराना कांग्रेसी महाभ्रष्ट, जालसाज, कृषि मंत्रालय में रहकर करोड़ों रुपये डकार चुका हैं। जालसाजियों, फर्जी लायसेंसों, फर्जी आयात, के लिये कुख्यात से उम्मीद करना कि वो जनता के साथ न्याय करेगा। जिनकी जिंदगी गुजर गयी भ्रष्टाचार, जालसाजी करते-2 अब उन्हें भगवान या न्यायाधिपति बनाने से आदतें तो नहीं छोड़ सकते। फिर कांग्रेसी को कांग्रेसी अम्मा ने ही बनाया राज्यपाल तो नाचेगे तो कांग्रेस के इशारों पर और आड़ लेगें कानूनों की शासन का धन बचाने की। धन बचे न बचे ये तो डकार ही लेंगे। जहाँ तक महाभ्रष्ट, डकैतों आई. ए. एस. लाबी का सवाल हैं, तो शासन में बैठे जनता के धन पर डाका डालने और डाका डालने के लिये कुख्यात हैं। उनसे अन्याय और पैसे की धुन पर नाचने की उम्मीद की जा सकती हैं। फिर वही सूचना आयुक्त संभागीय सूचना अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी बना दिये जाने क्या औकात हैं कि वो जनता को अपने विरुद्ध ही साक्ष्य देंगे और बतायेंगे कि हमने यहाँ इतना लूटा जालसाजी और भ्रष्टाचार किया। लोकतंत्र को बचाने के नाटक में पुनः लोकतंत्र की वास्तविकता में हत्या तक दी गयी।*

पृष्ठ 1 का शेष

## स्कापियन सौदा

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के प्रबंधन से लेकर टिकिट बुकिंग तक महाभ्रष्टों से भरा लुआ पूरा स्टाफ तो एयर बस खरीदने से उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा लूटपाट और वसूली करने का, पेट्रोल बेचने से लेकर उसके स्पेयर पार्ट्स की खरीदी बिक्री में। चूंकि जनता का पैसा है सीधा नहीं डकारा जा सकता इसलिए खरीदी के बहाने वसूली की जा रही है।

पृष्ठ 1 का शेष

## बहू के साथ मौंज

बला से कोई आत्महत्या करे, तो पुलिस के डंडों से मरे गिद्ध को तो माँस चाहिए मरे या जिंदे का।

लंदन की विदेश यात्रा में गौर उसकी बहू कृष्णा गौर जिसको लेकर वल्लभ भवन के गलियारों से लेकर पूरी राजधानी के गली-मोहल्लों में ससुर बहू के संबंधों को लेकर पिछले वर्ष भर से चर्चा का विषय रहता है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि बाबूलाल गौर और बहू कृष्णा गौर के संबंधों के मानसिक तनावों से बेटे की अकाल मृत्यु हुई है। वसे भी यादवों के खानदान में राधा, कृष्ण की रिश्ते में मामी थीं और उम्र में काफी बड़ी थी पर राधा-कृष्ण के संबंध सहस्त्रों शताब्दियों से जग जाहिर हैं। फिर विधवा बहू और अनुभवी, अक़्खड़ विधवा ससुर बाबू ने अपनी और उसकी एकाकी जिंदगी में सामंजस्य बैठा लिया। यही कारण था कि पहले उसे बिना भाजपा सदस्यता के पर्यटन का अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण उर्फ नीतिश भारद्वाज को हटा कर अपनी (बहू) श्रीमती कृष्णा को बना दिया। जब ज्यादा हो हल्ला मचा बात राज्य की राजधानी देश के दिल ही तकपहुंच गई तो उसे बड़े भारी दिल से हटाया। अब जब बाबू गौर का दिल 24 घंटों की उठापटक से बिचकने लगा तो निवेश का बहाना पक़ड, वाणिज्य मंत्री कैलाश चावला को छोड़ बहू कृष्णा गौर को लो गए वो तो कांग्रेसियों और मूल रूप से दिग्गी दानव ने छोड़ दिया वना लंदन के जिस होटल में रुके उस होटल से अगर इनकी फिल्म उतरवाकर मंगवा लेता तो स्तिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती और दिग्गी ये करने में सक्षम था।

यहां प्रदेश में शिक्षक, कर्मचारी, हड़ताल पर चले जाएं और पूरा प्रदेश बंद कर दें वो तो अय्याशी और मौज-मस्ती कर ले जनता के पैसे से कल रहें न रहें।

# आखिर आई.ए.एस. चुरकटों को ही बनाया सूचना अधिकारी

**आखिर चुरकटों को ही बनाया सूचना अधिकारी**

म.प्र. शासन में मुख्य सचिव से जिलों के अंतिम स्तर तक मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रूप में बैठी भ्रष्ट, हरामखोर, निकम्मी, अय्याश, लुटेरी, कामजोर इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को भारत शासन द्वारा लागू हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियम के प्रभावी होने के दिनांक 15 जून 2005 से 120 दिन के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जो कि अधिनियम क्र. 22-2005 की धारा 2, के द के अनुसार धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु म.प्र. शासन ने सचिव राजस्व को प्रथम अपीलेट अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

अर्थात ये हरामखोरों की फौज अपने पुराने ढर्रे के अनुसार पुनः स्वतंत्र हो गई है। ये शूकरों की फौज ऐसे हर पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल देगी।

संभागीय अधिकारियों के रूप में संभागीय आयुक्त ही सार्वजनिक सूचना अधिकारी होगा। पूर्व में भी ए.के. दास जो संभागीय आयुक्त है। को अनेकों पत्र दिए, पर महाभ्रष्ट छोटे भ्रष्टों को कैसे फंसायेगा। वो जालसाज तो पहले उन्हें बचायेगा। तो रु. 250 प्रतिदिन और रु. 25000 दंड कौन देगा? क्यों देगा? क्योंकि वही तो उसकी कमाई का आधार है। दूसरा जो महाभ्रष्ट है वही सर्वोच्च अधिकारी है।

राष्ट्र के केन्द्र में शासन में बैठी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जब सूचना का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2005 में तैयार कर लागू करने की बात कही तो लगा था कि शायद जनता के हित में कुछ करने की इन्होंने भाजपा की सरकार से सीख ली है, परन्तु इसके विपरीत सूचना के अधिकार को 15 जून 2005 को पूरे देश राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के साथ लागू कर दिया गया। इसके साथ ही 21 जून 2005 को भारत शासन के अधिसामान्य गजट के भाग II में इसको प्रकाशित कर 15 जून 2005 से अस्तित्व में आना लिखा गया।

15 जून 2005 से 120 दिन अर्थात 4 माह में केन्द्र व राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगी जिसमें संभागीय सूचना अधिकारी जिला स्तर पर सूचना अधिकारी होने चाहिए।

120 दिन अर्थात 12 अक्टूबर 2005 तक ये सभी अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 2 (स) के अनुसार इसकी धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्र व राज्य स्तर पर नियुक्त कर दिये जाने चाहिए। धारा 12 के अंतर्गत उप धारा (5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसके पास कानून और विधि का वृहत ज्ञान व अनुभव हो, विज्ञान व तकनीकी विशेषज्ञ हो, प्रबंधन पत्रकारिता, वृहत प्रचार माध्यमों, प्रशासनिक या राज्य कार्य किए हों, परन्तु धारा 12 की उपधारा (6) के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं बन सकेगा जो लोक सभा का सदस्य, विधान सभा का सदस्य या किसी कार्यालय में लाभ के पद पर बैठा हो या किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ा हो या किसी व्यवसाय या किसी पेशे से जुड़ा पद संभाल रहा हो

इस धारा की व्याख्या में जो भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यों की विधानसभा का सदस्य हो, राज्य या केन्द्र में लाभ के लिए किसी कार्यालय से न जुड़ा हो, किसी व्यवसाय या पेशा न कर रहा हो।

इसके विपरीत हाल ही में म.प्र. शासन ने धारा 12 के अंतर्गत राज्य के राजस्व आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त, सहा. आयुक्त को सहा. आयुक्त, संभागीय आयुक्त राजस्व को संभागीय सूचना अधिकारी और जिलाधीश को जिला सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर इन भ्रष्ट, चुरकटों, हरामखोरों की फौज को आईएम सेफ की परिभाषा को पुनः परिभाषित कर इन भ्रष्टों, जालसाजों को बचा दिया है। जबकि इस यर्थाथ को न केवल राजनैतिक वरन जनता भी जानने लगी है कि ये ही वह गिद्धों का गिरोह है जो एक तरफ जनता के द्वारा दिये धन को अप्रत्यक्ष रूप से और जनता से प्रत्यक्ष रूप से अरबों डकार जाते हैं।

जब इन्हीं को ही अधिकार सौंप दिये हैं तो इनके विरुद्ध कैसे प्रतिदिन रु. 250 से रु. 25000/- तक दंड के रूप में वसूले जा सकेंगे। इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 10 के बिन्दु 1 में इस बात का भी उल्लेख है कि दंड के रूप में समय सीमा समाप्त होने पर रु. 250/- प्रतिदिन और अधिकतम रु. 25000/- का दंड लगाया जा सकता है जो सेवा निवृत्ति में भविष्य निधि से भी काटा जा सकता है। परन्तु जब सारे चोर-चोर मौसेरे भाइयों की फौज हो बैठी हो तो कौन किस पर दंड करेगा।

जब अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि लाभ के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को नहीं बैठाया जाएगा तो फिर इन चुरकटों की लाबी को ही क्यों मुख्य सूचना अधिकारी से जिले तक का अधिकारी बना दिया गया। क्यों नहीं प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विधि विशेषज्ञ, विज्ञान तकनीकी विशेषज्ञ, प्रबंधन, पत्रकारिता, वृहत प्रसार व संचार माध्यमों के विशेषज्ञों को यह पद सौंपा गया।

जिन डकैतों के भ्रष्टाचार पकड़ने, जानकारी एकत्रित करने के लिए कानून बनाया गया उन्हीं महाभ्रष्टों, लुटेरे जालसाजों को मुख्य सूचना आयुक्त से जिला सूचना अधिकारी तक बना दिया। क्या किया इन हरामखोर, अय्याश निकम्मे, अवैध वसूली करने वाले अपराधियों, माफ़ियाओं के सरगना इन सफेदपोश शासकीय आपराधिक कुकृत्य करने वालों का पिछले 5 वर्ष में इंदौर उज्जैन, भोपाल, जबलपुर संभागों और इनके जिलों में लगभग 2000 से ज्यादा पत्र देने के बाद कितनों के जवाब इन्होंने, इनके अंतर्गत मातहत जिलाधीशों व जिला अधिकारियों ने फिर इनकी औकात ही क्या है जो उनसे जवाब मांगकर हमारे पत्रों के उत्तर देंगे या सारे शूकर भी उन्हीं की वसूली गंदगी चाट कर अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। फिर आई.ए.एस. का तो पुराना शगल है जहाँ भी लूटो, झाड़ो, पोंछो, साल दो साल में स्थानांतरण होगा, जो आयेगा उसे धोने दो जो इहोंने भ्रष्टाचार की गंदगी फैलायी, चाटी पौंछी आने वाला जाने।

मूल यह है इस कथा का, कि सुचना के अधिकार से इन भ्रष्टों के कुंडली मारकर अधिकार उपयोग करने तक न तो सूचनायें पूरी, सही और समय पर मिलनी है न भ्रष्टों के खिलाफ रु. 250 से 25000/- तक का दंड होना है।5 वर्ष की जंग लड़कर लगातार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ई-मेल और समाचार पत्र से दंड की व्यवस्था तो लागू करवा दी पर इस इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के चुरकटों से मुक्ति नहीं मिली, जंग जारी रहेगी, इसी विश्वास के साथ हम होंगे कामयाब।

## अधिनियम के विशेष तथ्य

◎अधि क्र. 22/2005, 28 अप्रैल 05 को पारित 15 जून 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़ पूरे भारत पर लागू।

◎20 वर्ष तक के स्तावेज, फाइलें ई-मेल, बजट, प्राक्कलन आदि सब कुछ मांगा जा सकता है। 20 वर्ष से पुराने मांगने पर उपलब्धता और संबंधित अधिकारी की मर्जी पर वह भी मिल सकता है।

◎सूचना न दिये जाने पर अवांछित, झूठी, गलत जानकारी देने पर रु. 250 प्रतिदिन और अधिकतम रु. 25000 के दंड की व्यवस्था।

◎केन्द्र व राज्य स्तर पर अलग मुख्य सूचना आयुक्त संभाग स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान जो 120 दिन में कर दी जानी चाहिए।

◎सूचना मांगने वाले को सूचना न दिये जाने पर खर्चे की भरपाई की व्यवस्था।

◎भारत का कोई भी नागरिक ऐसी सूचनाएंप्राप्त करने का अधिकारी

◎ म.प्र. शासन ने उसी महाभ्रष्ट चुरकट, जालसाज, अय्याश, महाहरामखोर आई.ए.एस. लॉबी की ही नियुक्ति कर दी जो लाभ के पदों पर बैठकर लाभार्जन कर रहे हैं। उनके विरुद्ध वो सूचना कैसे और क्यों देंगे। अर्थात अधिनियम पूरा बकवास हो गया।

पृष्ठ 1 का शेष

# कांग्रेसी व कम्युनिस्ट जन्म से देशद्रोही

पड़ी रसियन आर्टीलरी के टैंक, जहाज, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियों की खरीद की गई थीं। जबकि दुनिया के सड़े से देशों में भी एके 47 एके 45 राइफलों के अतिरिक्त कुछ नहीं बिकता। बस क्रेमलिन आपने माल को बेचने और भारत से दवाइयां, मसाले, सत्ता गार्मेन्ट व अन्य सामग्री आयात कर अपना कबाड़ा किलो के भाव से तांबे के मोल भारत में बेच कर कांग्रेसियों और पश्चिम बंगाल में बैठी सरकारों के माध्यम से जासूसी करने, सरकारें पलटाने, पं. बंगाल को लाल झंडे की आड़ में उद्योगपतियों, शासकीय, उद्यमों, शासकीय कार्यालयों में उत्पादन बाधित कर हड़ताल करवाने की अहं भूमिका केजीबी और रसियन दूतावासों ने निभाई है।

वैसे भी कम्युनिस्टों ने परतंत्र राष्ट्र मं भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। आजादी के बाद भी रसियन देश में पैर जमाए रखने के लिए एक तरफ कम्युनिस्टों को मुक्त हस्त से धन लुटाते रहे और कम्युनिस्टों को देश घुमाने के बहाने चाहे वो ज्योति बसु, बुद्ध देव, भट्टाचार्य, कारंत, हरजीतसिंग, भारत शासन में एजेंटों की तरह उपयोग करते रहे। ये केजबी ही थी जब पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो मोरारजी के गले में कैमरे में जासूसी उपकरण लगा कर हर बात की रिकार्डिंग करते रहे और मधुलिमये के रुस घूमकर आने के बाद ही मधुलिमये ने सरकार गिरराने में अहम भूमिका अदा की थी।

हर विदेशी सरकार चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस-फ्रांस, इटली और पूरे यूरोप की चाहत का केन्द्र क्यों शुरू से ही कांग्रेस सरकार रही है क्योंकि कांग्रेसी भ्रष्टों ने कदम-कदम पर राष्ट्र को दांव पर लगाकर अपनी जेबें भरने और राष्ट्र बेचने में अपनी अहं भूमिका अदा की है। ज्योति बसु के जीबी ने कांग्रेस पर सीआईए से पैसा लेने तो सोनिया ने जानबूझकर मार्क्सवादी कम्युनिस्टों पर रूस से पैसा लेने का आरोप लगाकर जो कड़ुवी सच्चाइयां उजागर कर अपनी छवि धोने का प्रयास कर यह तो सिद्ध कर दिया कि इन हरामखोर शूकरों का चरित्र कितना घिनौना है। कैसे ये गिद्धों की फौज एक तरफ देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, शकर, प्याज की कालाबाजारी कर जानता को लूटती है तो दूसरी तरफ देश के नाम पर कर्जे लेकर स्वयं धन डकारती है तो तीसरी तरफ विदेशियों के हाथ बिककर राष्ट्र की गोपनीयता भंग कर अपने बैंक बैलेंस बढ़ाती और देश विदेशियों के हाथ गिरवी कर देती है।

देश का बुद्धिजीवी जो अपने आपको बहुत महान समझता है वोट देने नहीं जाता कांग्रेसी षड्यंत्रकारी पाउच बांटकर झुग्गी बस्तियों में वोट कबाड़ सत्ताधीश बन कर बैठ जाते हैं। ये ही वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने स्वार्थों में लिप्त हो अपनी अय्याशी मक्कारी में उलझा रहता है। सब जानकर भी जिसने 3000 वर्ष देश को गुलाम रखा और फिर धूर्त कांग्रेसी कम्युनिस्ट गिद्धों के हाथों देश का गिरवी होते देख रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कौन देश को कहां बेच रहा है गिरवी रख रहा है।

उसे तब भी फर्क नहीं पड़ा था जब इंदिरा जिमी कार्टर के व्हाइट हाउस में सोयी थी। उसे तब भी फर्क नहीं पड़ा जब उसकी बीवी किसी गली के गुंडे के साथ रात गुजार कर आती है। वह तो उस गुंडे के संरक्षण में ही अपने आपको सुरक्षित समझने लगता है क्योंकि वह गुंडा उसकी बीवी के नाड़े से बंधा हुआ है। वही हाल इस देश का राजनीतिक वर्ग कर रहा है। भाजपा अपने विवादों में उलझी है। उससे मुक्ति पाए तो देश की सोचे।

साप्ताहिक समय माया

# दास्ताने श्रीमती सलीना सिंग खाद्य एवं औषधि नियंत्रक

**जब नियंत्रक ही मिलावटियों को संरक्षण दे तो खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अपनी दवा दुकानें और फैक्ट्रियां चलाएंगे**

म.प्र. में जिस श्रीमती सलीना सिंह को भ्रष्टाचार और वसूली के कारण पूर्व में खाद्य एवं औषधि नियंत्रक पद से हटाया गया था वो पुनः इसी पद पर बैठा दी गई। गौर केवल वसूली पर गौर फरमाते है और कुर्सी की चिंता में डूबा रहता है। स्वाभाविक है उसके प्रशासनिक अधिकारी हर विभाग में क्या काला-पीला कर रहे हैं। वसूली के लिये दो चार जगह छापे मारे। दूसरे बड़े महा भ्रष्टों को धमकाया और सीधे वसूली लाखों में की गई। जो नकली घी की पीला कर रहे हैं। वसूली के लिये दो चार जगह छापे मारे। दूसरे बड़े महा भ्रष्टों को धमकाया और सीधे वसूली लाखों में की गई। जो नकली घी की बदनाम मक्सी की शुभम घी के अग्रवाल की मिली जानकारी के अनुसार साल में रु. 2 करोड़ की सीधी रिश्वत देता है। इसलिए घी की उस फैक्ट्री पर कोई छापा नहीं मारता, फिर उन्हें भी तो वसूली करनी है कारों में घूमना है। भले ही वो दामाद के नाम से नगद रु. 4 लाख 65 हजार में खरीदी गई हो।

डी.के. जैन औषधि निरीक्षक यदि ओर डील लेबो. लि. जिसे भतीजे के नाम से चलाया जा रहा है सांवेर रोड पर। फिर लगभग अधिकांश ड्रग इंस्पेक्टरों की थोक व फुटकर की दवा दुकानें दवा बाजार में या घर से चलाई जा रही हैं। धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम के अधिकांश औषधि निरीक्षक बस रु. 30 हजार लेकर धड़ल्ले से बिना कानून कायदों को ध्यान में रखे लायसेंस बांटने में जुटे हैं। नियंत्रक कानून दिखाने नहीं पूरे प्रदेश से वसूली को आई हैं, वो महाभ्रष्ट, उसकी बला से नकली दवाएं, स्तरहीन मिलावटी, कुछ भी बनाएं और बेचें इसे तो बस रोकड़ा पहुंचा दें।

वर्तमान में म.प्र. की खाद्य एवं औषधि नियंत्रक पद पर पुनः शोभा बढ़ाने वाली सलीना सिंग कैसे इन पद पर पुनः आयी जबकि भ्रष्टाचार और करोड़ों की वसूली के आरोप में ही उस पद से हटाई गई थी। सूत्रों के अनुसार पूर्व का कांग्रेस का भ्रष्ट कृषि मंत्री वर्तमान में म.प्र. की सरकार का राज्यपाल है के यहां उक्त महिला को सीधा प्रवेश मिलता है। उन्हीं के सिफारिश पर ये इस वसूली के पद पर रु. 25 लाख देने के बाद शोभायमान है जैसा कि कार्यालयीन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। भ्रष्ट कांग्रेसी गिद्धों की फौज को तो नोचने-खसोटने के लिये ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है फिर कांग्रेस तो लंपटों, भ्रष्टों, गुंडों, अपराधियों की फौज का नाम है। कांग्रेस यदि उनका व्यक्ति राज्यपाल बन जाए या राष्ट्रपति अपनी वसूली, अय्याशी, भ्रष्टाचार के कुकर्मों से मुक्ति नहीं पा जाता। यही कारण है कि भ्रष्टों को भ्रष्ट ही पसंद आते हैं। इस कारण राजभवन से पहुंची सिफारिश के अंतर्गत सलीना सिंग पुनः खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर बैठा दी गई। बैठते ही साथ उसी पुराने रूप को सुधार कर अब एक किसी छोटी फैक्ट्री या फैक्ट्रियों पर छापा मारो उसके पूर्व मीडिया को रु. लाख दो लाख की गड्डी फेंकों और कर्मठ, कड़क, ईमानदारी की झलक दिखाओ फिर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री जो वर्ष भर में लाख दो लाख देती है अपने आप रु. 10 लाख देगी। बड़े भ्रष्टों से खेल करोड़ों में कर लिये जाते हैं। मक्सी की शुभम घी फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल यदि सीधे ही रु. 2 करोड़ नहीं तो रु. 1 करोड़ भी पहुंचायेगा तो बाजार में विशुद्ध नकली माल ही बेचेगा रु. 100 करोड़ से ज्यादा का तब तो रु. 50 करोड़ कमायेगा। भोपाल के सूत्रों के अनुसार अब यह नियंत्रक करोड़ों रुपये अपने चम्मचों के माध्यम से वसूलती है। जब नियंत्रक ही भ्रष्ट हो तो औषधि और खाद्य निरीक्षक पूर्व से ही महा भ्रष्ट हैं। वो तो खुले में रु. 3 हजार के लायसेंस के रु. 30,000 लेते हैं। निःसंदेह पैसा हर जिले के उपजिलाधीश और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी पहुंचता है। यही कारण है कि इस जिले के महाभ्रष्ट महानिकम्मे के.के. विजयवर्गीय को यह जानने के लिए पत्र दिया गया था। सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्योंकि वह यहां के खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण विभाग का उपसंचालक भी है कि कितने औषधि विशेषज्ञ (फर्मासिस्ट) म.प्र. फार्मेसी कौंसिल के सदस्य हैं। क्योंकि एक ही औषधि विशेषज्ञ या भेषजज्ञ के पंजीयन पर 4 से औसतन 6 औषधि फुटकर विक्रेता दुकान चला रहे हैं। जो कि सरासर गैर कानूनी है जबकि यह स्थिति धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास में और भी दयनीय है। यही हाल रसायनज्ञों के भी हैं। जिन्हें हाल ही में आशीष त्रिवेदी ने साक्षात्कार लेकर पंजीयन हेतु भेजा है। जिन्होंने रुपये 10,000 दिए हैं। स्वाभाविक है पंजीयन उन्हीं का होगा साक्षात्कार में भी उन्होंने ही उत्तीर्ण किया होगा, धार, झाबुआ के औषधि निरीक्षक भी वर्तमान में रु. एक करोड़ की चल-अचल सम्पत्ति का मालिक है। कारें मोटर सायकलें, स्कूटर, बंगला कैसे कमाया गया होगा। स्वाभाविक है कानून को ताक पर रखकर लंबा खेल किया जा रहा है। दूसरी ओर डी.के. जैन औषधि निरीक्षक ने तो ओरडील लेबोरेटरीज लि. नाम की पूरी दवा फैक्ट्री ही सांवेर रोड पर खोल रखी है। सलीना सिंग या अन्य औषधि निरीक्षकों ने इस फैक्ट्री पर कितनी बार छापा मार कार्यवाही की। सभी औषधियाँ जो ये फैक्ट्री बना रही है उनके नमूने लिये गये नहीं, सभी के पेटेंट राइट्स इसके पास है या नहीं? क्या ये पेटेंट राइट अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रही? सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। इसका केमिस्ट फार्मासिस्ट कौन है। स्वयं डी.के. जैन या ये भी फर्जी नाम का किसी का उपयोग कर रहे हैं। फिर सेवा पुस्तिका में ये स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी औषधि निरीक्षक औषधियों के उत्पादन व्यापार से नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर किसी की ब्ल्यू आइस की दवाओं की दुकान कैसे चल रही है। यही हाल खाद्य निरीक्षकों के हैं। हाल ही में महीनों से गायब देवास की खाद्य निरीक्षक को निलंबित किया गया है क्योंकि इस खाद्य निरीक्षक महिला के महीनों पते ही नहीं रहते हैं। सबके पास कारें, बंगले कैसे आए एक को चमकाओ नमूने लो दस से खुली वसूली करो। फिर नियंत्रक खुलेआम वसूली करेगी तो निरीक्षकों को तो खुली छूट मिलेगी ही जनता का कुछ भी खिलाये पिलाये औषधि और खाद्य वस्तु उत्पादक विक्रेता जनता तो मरने के लिए पैदा ही हुई है।

### सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का पत्र देखते ही भड़क जाते हैं

# जिला पंचायतों के मु.का.अ. महाभ्रष्ट और जालसाज

## सरपंचों को हर कार्य की राशि का आबंटन से पहले रोकड़ा ले लेते हैं।

**गांवों के विकास पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें पूरे वर्ष भर में रु. 5 लाख व करोड़ से ज्यादा खर्च करती हैं। जिसने ग्रामीण विकास और ग्रामीणों के विकास के लिए हर क्षेत्र में यथा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने योग्य जल और जल-नल निकासी गांवों में सड़कें, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, सिंचाई, सहकारिता, बागवानी व अन्य क्षेत्रों में निवेश कर ग्रामीण विकास कार्य किये जाते हैं। इन सब विकास कार्यों में जिलाधीश और उसके अधीनस्थ उपजिलाधीश स्तर का जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर वर्ष अरबों रुपये डकार जाते हैं।**

सरपंचों को दिये जाने वाले अंत्योदय योजना का स्कूलों के दोपहर भोजन का गेंहू, सड़कों, तालाबों, स्टाप डेमों, नहरों, ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी आदि के केन्द्र व राज्य सरकारों के स्वीकृत कामों की मिलने वाली राशि का चेक देने से पहले ये शूकरों और श्वानों की फौज 10 से 40% नगद लेकर डकार जाती है। इंदौर जिला पंचायत का मु.का. अधिकारी मह्भ्रष्ट जालसाज आशुतोष अवस्थी, देवास का केदार शर्मा, धार का ई. रमेश कुमार, उज्जैन का महेन्द्र ज्ञानी, झाबुआ का पुरुषोत्तम धीमान, खरगोन का रवि डाफरिया बड़वानी का अशोक राय, खंडवा का निसार अहमद, नीमच का अशोक देशवाल, मंदसौर का मुकेश शुक्ला, शाजापुर का टी. सीमहावर, रतलाम का पवन शर्मा, जबलपुर का राजेश व झाबुआ व अन्य म.प्र. के सभी जिलों के पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियं को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त जाँच करवा दी जाये तो घोटालों में 10 अरब के आंकड़े मात्र 3 वर्ष में ही सामने आ जाएंगे।

इंदौर। जिला पंचायतों में बैठा हर जिले का मुख्य कार्यपालन हर जिले की 500 से 700 ग्राम पंचायतों के विकास का कर्ताधर्ता होता है। परन्तु पंचायतों के विकास के नाम पर ये महाभ्रष्ट शूकरों की फौज अवश्य अरबपति हो जाती है। सरपंचों को तालाब, सड़कें, जल आपूर्ति के अन्त्योदय शिक्षा, बालवाड़ी जो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आता है, व अन्य कार्यों के लिए मिलने वाले धन में से 25 से 40% धन नगद लेकर ही चेक देते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण महिला और पुरुष मजदूरों के हिए गेंहू, मिट्टी तेल, दोपहर भोजन का गेंहू आदि भी टनों से मिलता है वह भी सरपंचों को मुफ्त में नहीं वरन काम के बदले अनाज अत्यधिक गरीबों को आपात काल में हर पंचायत के सरपंच को प्रति माह 11 क्विंटल गेंहू दिया जाता है ताकि कोई भी ग्रामीण भूखा न मरे। 8 से 20 किलो गेंहू तक एक परिवार को मुफ्त में दिया जाता है। फिर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2 रु. किलो गेंहू, 3 रु. किलो चावल देने की व्यवस्था भी राशन कार्डों पर रहती है जिसका आबंटन भी मुख्यकार्यपालन अधिकारी को सौंकड़ों टन मं मिलता है इसका भी आबंटन राशन दुकानों का मुठ्ठी गर्म करने पर ही मिलता है। ये सारा गेंहू जो राज्य व केन्द्र सरकारों के कोटे से अलग-अलग मदों में अलग व कुछ योजनाओं में संयुक्त रूप से मिलता है परन्तु धूर्त शातिर मक्कार जिलों की पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष को रबर स्टाम्प बनाकर कुछ टुकड़े मात्र 2 से 2% उछालकर बाकी स्वयं जीम जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण इंदौर का मुख्य का. अधिकारी आशुतोष अवस्थी, धार बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, खंडवा जो आदिवासी जिलों की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों में केन्द्र व राज्य सरकार के आदिवासियों के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, सड़कों, तालाबों, कृषि व अन्य कार्यों के लिये विशेष सुविधा युक्त पैकेज दिये जाते हैं। के कार्यपालन धार में ई. रमेश कुमार, झाबुआ में पुरुषोत्तम धीमान, खरगोन में रवि डाफरिया, बड़वानी में अशोक राय, खंडवा में निसार अहमद इन आदिवासियों के विकास का अधिकांश पैसा अनपढ़ सरपंचों से अंगूठा लगवाकर स्वयं ही डकार जाते हैं। इन हरामखोर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की जाँच की जाये तो अरबों की चल-अचल संपत्ति जो इनके बीवी बच्चों, भाइयों, माता-पिता से लेकर सास-ससुर, साले-सालियों के नाम से निकलेगी।

निःसंदेह इन जिलों के सांसदों और विधायक भी श्वानों को दिये जाने वाले टुकड़ों की तरह का धन डकार कर न केवल चुप रहते हैं वरन जानबूझकर विकास भी नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी सोच और कहना रहता है कि जब तक ये गरीब और अविकसित ग्रामीण हैं तभी तक इन हरामखोर मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की पूछ-परख है। साथ ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों का पैसा मिलता रहेगा।

यही वस्तुस्थिति उज्जैन संभाग के जिलों की है। उज्जैन का मुख्यकार्यपालन अधिकारी महेन्द्र ज्ञानी, नीमच का अशोक देशवाल, मंदसौर का मुकेश शुक्ल, शाजापुर का टीसी महावर, रतलाम का पवन शर्मा, देवास का केदार शर्मा के साथ ही पूरे म.प्र., बिहार, उड़ीसा, उ.प्र. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के जिलों की है। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडू, पश्चिम भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों की स्थिति 25% तक बेहतर है।

केन्द्र व राज्य शासन में बैठे मंत्रिगण चाहें तो इस स्थिति में बेहतर बदलाव मात्र इन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के हर दो वर्ष में स्थानांतरण और दूसरी बार एक उपजिलाधीश स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी न बना कर भी ला सकते हैं परन्तु भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को भी पैसा चाहिए, इसलिए वो महाभ्रष्टों को मुख्य का. अ. बनाकर स्वयं भी मोटा पैसा कमाते हैं।

इंदौर के मु.का.अ. आशुतोष अवस्थी, देवास के केदार शर्मा, धार के ई. रमेश कुमार, झाबुआ के पुरुषोत्तम धीमान को सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्र दिये गये परन्तु ये शूकरों की फौज निगल गई। फिर अपने ही भ्रष्टाचार के प्रमाण कैसे दें। पर बकरे की अम्मां कब तक खैर मनाएगी। 12 अक्टूबर 05 केन्द्र व राज्य सरकार का अधिकारी हर जिले और संभाग स्तर पर इसी काम को देखेगा और पत्रोत्तर न देने पर रु. 25000/- तक का जुर्माना वसूलेगा।

### महिला बाल विकास भ्रष्टों का अड्डा

# भागी गई औरतों के आरोप बिल्कुल सही

पलासिया स्थित महिला उद्धारगृह से भागी युवतियों ने जो आरोप लगाये न केवल बिल्कुल सही थे वरन् कमजोर भी थे, उन पर ज्यादितियों और यौन शोषण का अड्डा वरन शुद्धता शासकीय वैश्यालय था जिसमें से शाम प़डते ही दरबाजा खुलता था उसमें पुलिसियों से लेकर नेताओं और गुंडों की हवस पूर्ति का शासकीय वैश्यालय था.

श्रीमती अंजू शाह उस उद्धारगृह की अधीयिका से लेकर महिला बाल विकास में बैठी तृप्ति त्रिपाठी ने आरोपों को जिस तरह से नकारा तो स्वयं ही सच्चाई प्रगट करता हैं। फर्जी संस्थओं निजी क्षेत्रों में नेताओं और महिला नेत्रियों की अगुआई में चल रही हैं। जो संस्थायें शासन की अगुआई में चल रही हैं। इन सभी में भारी वित्तीय हेरा फेरियाँ होती हैं। वहाँ बैठी लेखाकार श्रीमती मंजु जैन भी भ्रष्टाचार में किसी से पूछे नहीं। कुछ माह पहले उसने जो लाखों का मकान खरीदा उसके लिये रु.7-8 हजार वेतन कमाने वाली के पास धन कहाँ से आया। सूचना के अधिकार अधिनियम 1998 और 2005 के अंतर्गत दिये गये पत्र का मिडिया वर्ल्ड कम्युनिकेशन को आज दिनांक तक कोई जबाव नहीं दिया।

वैसे भी पूरा महिला बाल विकाह कार्यालय जिसका आयुक्त महाभ्रष्ट अय्याश सुधिरंजन मोहंती हैं। फिर इंदौर में भी वही महिला जिला अधिकारी के पद पर बैठ सकती हैं। जो सारे नारीयों के लटके झटके दिखाने, धन डकारने और ऊपर पहुँचाने में संक्षम हो।

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से दहशत

# वाणिज्यकर सूचना कार्यालय तीसरी मंजिल पर

**म.प्र. वाणिज्य कर के आयुक्त से चपरासी तक हैं तो सब भ्रष्टाचार की गंदगी चाटने और लोट लगाने के शौकीन**

वाणिज्य करायुक्त पी.के. दास तो बड़ी इमानदार हैं पर चरित्र में और व्यवहार में वैसी ईमानदारी झलकती नहीं है। यदि चरित्र और व्यवहार में ईमानदारी होती तो म.प्र. वाणिज्य कर मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2003 के अंतर्गत सूचना कक्ष धरातल पर मुख्य द्वार के समीप ही कहीं बनाया जाना चाहिए था। यदि कक्ष खाली नहीं भी था तो कक्ष एक खाली करवा कर जहां वर्तमान में तीसरी मंजिल पर कक्ष निर्मित किया है वहां नीचे के कक्ष का सामान पहुंचाकर व्यवस्थाएं की जा सकती थीं।

इसके विपरीत भ्रष्टों और हरामखोरों की फौज ने न केवल तीसरी मंजिर पर कक्ष खोला बल्कि वहां बैठने वाला संजय जैन भी ऐसे निकम्मे को नियुक्त किया जो साढ़े चार बजे शाम से ही गायब हो जाता है। विभाग के अन्य सभी भ्रष्टों की तरह इसका भी लंच 1 बजे से शुरू होकर तीन बजे तक चलता रहता है।

यदि थोड़ी सी भी विभाग के प्रति भ्रष्टों और हरामखोरों आयुक्त से लेकर अन्य सभी कर्मचारियों में निष्ठा और सम्मान बचा हो तो न केवल सूचना कक्ष भूतल पर बनाएं वरन इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले पत्रों का त्वरित गति से निराकरण करें।

पृष्ठ 6 का शेष

# जालसाज स्कूलों की मान्यतायें र- क्यों नहीं?

खून, सुरी-सुंदरी और धन का ये सब तो वही दे सकते हैं जो स्वयं जालसाजी करें शिक्षिकाओं की जगह शिक्षित औरअय्याश महिलाओं को नौकरी पर रख खुद भी अय्याशी करे और जालसाजी पूर्ण कार्यो को अंजाम देने के लिये सुरा के साथ सुंदरीयाँ भी पेश करें तो फिर कौन सी कानून, कैसा कानून एक नहीं सौ अपराध करों सब माफ। नहीं 100 की छात्रवृत्तियाँ डकारों, परीक्षा के या प्रवेश के फार्म की अंतिम तिथि के 2 महीने बाद भी जमा करो, बाबु अधिकारी, अध्यक्ष जमा नहीं करे तो सुरा सुंदरी का भोग लगाता भ्रष्ट सचिव और मंत्री से करवा लेंगे। फिर ऐसा स्कूल एक कमरे में ही क्यों न चल रहा हो सब चलेगा।

परीक्षा न भी दो हो, तो जाली मार्कशीट और प्रमाणपत्र से कॉलेज में सीधा प्रवेश दिलवा दिया जायेगा शासकीय में नहीं तो गली मोहल्ले के नुक्क़डो पर चाय पान की तरहा कॉलेज भी चल रहे हैं। चिंता न को, पैसा रखो परन्तु भ्रष्ट अय्याश यु के सांभल से जब अय्याश और विक्षा सचिव हो तो यह नियतितों म.प्र. की शिक्षा की होनी ही हैं। लेकर अन्य सभी कर्मचारियों में निष्ठा और सम्मान बचा हो तो न केवल सूचना कक्ष भूतल पर बनाएं वरन इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले पत्रों का त्वरित गति से निराकरण करें।